E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 07-04-2026
Accepted: 14-05-2026
Published: 04-07-2026

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 4; Issue 3; 2026; Page No. 06-14

ग्रामीण समाज में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका चमोली जिले के संदर्भ में

डॉ. अनुज सिंह राणा

सहायक प्राध्यापक, बी.एड. विभाग, सनराइज एकेडमी मैनेजमेंट सोसायटी, (कॉलेज ऑफ एजुकेशन), देहरादून, उत्तराखंड, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21193724

Corresponding Author: डॉ. अनुज सिंह राणा

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र उत्तराखण्ड के चमोली जिले के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं सामाजिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। चमोली एक दुर्गम पर्वतीय जनपद है जहाँ शिक्षा की पहुँच ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। SSA के क्रियान्वयन के पश्चात् इस जिले में नामांकन अनुपात, ड्रॉप-आउट दर, अवसंरचनात्मक विकास एवं शिक्षक-प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। शोध में प्राथमिक (120 शिक्षक, 80 अभिभावक, 40 VEC सदस्य) एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि SSA ने ग्रामीण चमोली में सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु गुणवत्ता, भौगोलिक दुर्गमता एवं प्रवासन जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

मूल शब्द: सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण शिक्षा, चमोली, GER, ड्रॉप-आउट, अवसंरचना, RTE, पर्वतीय शिक्षा

1. प्रस्तावना

भारत में शिक्षा को जनसाधारण तक पहुँचाने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan – SSA) एक ऐतिहासिक एवं सुनियोजित राष्ट्रीय पहल है। वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ इस अभियान का मूल उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना था (MHRD, 2001)। 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) एवं 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE, 2009) के अधिनियमन के पश्चात् SSA को वैधानिक आधार एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा प्राप्त हुआ (Government of India, 2009)।

उत्तराखण्ड का चमोली जिला 7,520 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला एक पर्वतीय एवं आदिवासी बहुल जनपद है। यहाँ के गाँवों की भौगोलिक विषमता, कठिन मौसम, आर्थिक पिछड़ापन, अभिभावकों की निरक्षरता एवं मौसमी प्रवास की प्रवृत्ति शिक्षा के प्रसार में पारम्परिक रूप से बाधक रही हैं (Rawat & Negi, 2015) [26]। ऐसे विकट भौगोलिक-सामाजिक परिवेश में SSA ने शिक्षा की जड़ें किस सीमा तक जमाई हैं – यह एक प्रासंगिक एवं नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण शोध-प्रश्न है।

प्रस्तुत शोध-पत्र उसी प्रश्न का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक उत्तर खोजने का प्रयास है। इसमें नामांकन दर, ड्रॉप-आउट, अवसंरचना, शिक्षक-प्रशिक्षण एवं सामाजिक प्रभावों का बहुआयामी परीक्षण किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

सर्व शिक्षा अभियान एवं ग्रामीण शिक्षा पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अध्ययन उपलब्ध हैं। प्रमुख समीक्षाएँ निम्नवत् हैं:

Drèze & Sen (2002) [7] ने तर्क दिया कि ग्रामीण भारत में शिक्षा की निम्न गुणवत्ता एवं नामांकन की कमी का मूल कारण सामाजिक असमानता व राज्य की उदासीनता है। उनके अनुसार SSA जैसी योजनाएँ इस खाई को पाटने में सहायक हो सकती हैं।

Tilak (2004) [29] ने SSA की वित्तीय संरचना एवं राज्यों की क्रियान्वयन क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाया। उनका मत था कि वित्तीय अनुशासन के अभाव में SSA के लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं।

Ramachandran (2004) [25] ने SSA के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगभेद एक प्रमुख बाधा है। KGBV योजना इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

Kumar, Priyam & Saxena (2001) [12] ने DPEP (SSA का पूर्ववर्ती कार्यक्रम) की समीक्षा में स्थापित किया कि पर्वतीय राज्यों में भौगोलिक विषमता के कारण सामान्य मॉडल प्रभावी नहीं होता; स्थानीय अनुकूलन आवश्यक है।

Singh (2011) [28] ने उत्तराखण्ड में SSA की कार्य-प्रणाली पर शोध में पाया कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में SSA ने अवसंरचना में सुधार किया, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच सकी।

ASER (2022) [2] ने रेखांकित किया कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कक्षा 5 के लगभग 40% बच्चे कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं – जो गुणात्मक शिक्षा की चुनौती को उजागर करता है।

Mehta (2014) [14] के अनुसार पर्वतीय राज्यों में SSA की सफलता बहु-स्तरीय सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर है। ग्राम शिक्षा समिति (VEC) की भूमिका SSA के प्रभाव को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण रही है।

Govinda (2011) [10] ने शिक्षा में बहिष्करण की समस्या पर प्रकाश डाला और बताया कि SC/ST एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना SSA की सबसे बड़ी चुनौती है।

Jha & Jhingran (2005) [11] ने पर्वतीय राज्यों में अवसंरचना विकास को एक दीर्घकालिक चुनौती बताया और कहा कि एकल-शिक्षक विद्यालयों की समस्या का समाधान बिना राजनैतिक इच्छाशक्ति के सम्भव नहीं।

World Bank (2008) [35] ने SSA-II के मूल्यांकन में पाया कि भारत में प्राथमिक नामांकन में 95% की वृद्धि हुई है, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षक-उपस्थिति अभी भी चिन्ता का विषय है।

UNESCO (2014) [32] की EFA (Education for All) रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि भारत ने नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है परन्तु 'शिक्षा की गुणवत्ता' और 'सीखने के परिणाम' (Learning Outcomes) में अभी भी बड़ा अंतर है।

3. शोध के उद्देश्य

3.1 प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:

1. चमोली जिले के ग्रामीण विद्यालयों में SSA के अन्तर्गत नामांकन दर में हुई वृद्धि का विश्लेषण करना।
2. SSA के क्रियान्वयन से विद्यालयी अवसंरचना में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
3. ड्रॉप-आउट दर में कमी के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करना।
4. शिक्षक प्रशिक्षण एवं छात्र-शिक्षक अनुपात की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करना।
5. SSA के सामाजिक प्रभावों – बालिका शिक्षा, SC/ST एवं वंचित वर्ग – का परीक्षण करना।
6. SSA क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों की पहचान कर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध-पद्धति

4.1 शोध-प्रकार

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) प्रकृति का है। इसमें मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) दोनों पद्धतियों का समन्वित उपयोग किया गया है।

4.2 अध्ययन-क्षेत्र एवं न्यादर्श

अध्ययन का क्षेत्र चमोली जिले की चार विकासखण्डों – कर्णप्रयाग, गैरसैण, थराली एवं घाट – तक सीमित रखा गया है। उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि (Purposive Sampling) से 240 प्रतिभागियों का चयन किया गया जिसमें 120 शिक्षक, 80 अभिभावक एवं 40 ग्राम शिक्षा समिति (VEC) के सदस्य सम्मिलित हैं।

4.3 तथ्य-संग्रह के स्रोत

- प्राथमिक आँकड़े: संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं विद्यालय-भ्रमण अवलोकन।
- द्वितीयक आँकड़े: DISE रिपोर्ट, SCERT उत्तराखण्ड, जिला शिक्षा कार्यालय चमोली, ASER रिपोर्ट, MHRD, UNESCO एवं NCTE के प्रकाशन।
- सांख्यिकीय विश्लेषण: प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र, दण्ड-आलेख एवं वृत्त-चित्र।

5. सर्व शिक्षा अभियान: एक सिंहावलोकन

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार की एक समयबद्ध, विकेन्द्रीकृत एवं समुदाय-केन्द्रित योजना है जिसे 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) एवं RTE अधिनियम 2009 का वैधानिक आधार प्राप्त है। 2018-19 में SSA, RMSA एवं Teacher Education को 'समग्र शिक्षा अभियान' में समेकित किया गया (MHRD, 2018)। इसके प्रमुख घटक हैं:

तालिका 1: SSA के प्रमुख घटक एवं उद्देश्य

क्र. सं.	घटक	उद्देश्य
1	सार्वभौमिक नामांकन	6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना
2	अवसंरचना विकास	नये कक्षाकक्ष, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय का निर्माण
3	शिक्षक प्रशिक्षण	सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण, डाइट का सुदृढ़ीकरण
4	बालिका शिक्षा (KGBV)	वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय
5	समावेशी शिक्षा (CWSN)	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन व समावेश
6	सामुदायिक सहभागिता	ग्राम शिक्षा समिति (VEC) का सशक्तीकरण
7	मध्याह्न भोजन योजना	उपस्थिति एवं नामांकन बढ़ाने हेतु पोषण सहायता

(स्रोत: MHRD, 2007)

6. चमोली जिला: शैक्षिक परिदृश्य

चमोली उत्तराखण्ड का एक पर्वतीय जिला है जो हिमालयी परिक्षेत्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 3,91,605 है, जिसमें से 72.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है (Census of India, 2011)। यहाँ की साक्षरता दर 82.7% है। जिले में 12 विकासखण्ड हैं जिनमें से 9 दुर्गम श्रेणी में आते हैं।

तालिका 2: चमोली जिले के शैक्षिक आँकड़े (2000-01 से 2022-23) |

संकेतक	SSA-पूर्व (2000-01)	2010-11	2016-17	2022-23
प्राथमिक GER (%)	68.2	85.2	90.6	98.3
उच्च प्राथमिक GER (%)	51.4	71.5	79.8	91.7
माध्यमिक GER (%)	38.6	54.3	63.1	80.2
ड्रॉप-आउट दर (%)	22.8	14.6	9.3	5.7
बालिका नामांकन अनुपात	0.84	0.91	0.96	0.98
शिक्षक-छात्र अनुपात	1:42	1:35	1:30	1:24
प्रशिक्षित शिक्षक (%)	51	68	74	89
SC/ST बालिका नामांकन (%)	58.3	68.4	78.1	87.6

स्रोत: DISE 2022-23; DEO Chamoli

7. आँकड़ों का विश्लेषण

7.1 विद्यालयों का वर्गीकरण

चमोली जिले में वर्ष 2022-23 तक कुल 1,247 प्रारम्भिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें सरकारी, निजी एवं अन्य श्रेणियों के विद्यालय सम्मिलित हैं। निम्न पाई-चार्ट (चित्र 1) इस वितरण को दर्शाता है। सरकारी विद्यालयों का अनुपात 62% है जो SSA के सरकारी शिक्षा-सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को प्रतिबिम्बित करता है (DISE, 2022-23)।

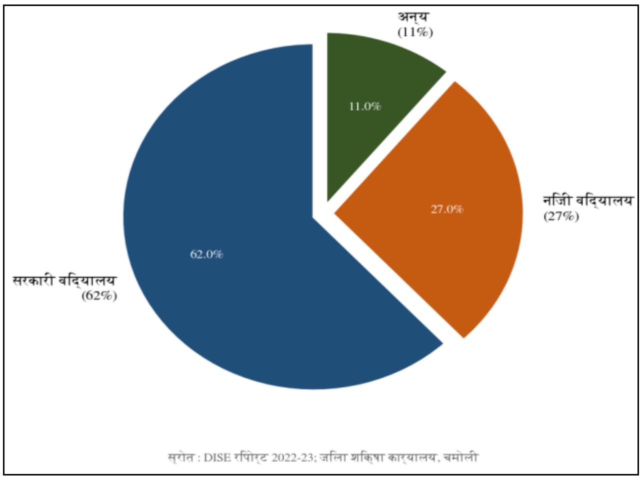

चित्र 1: चमोली जिले में विद्यालयों का वर्गीकरण (2022-23) |
स्रोत: DISE 2022-23

7.2 सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि

SSA के लागू होने के पश्चात् चमोली जिले में सकल नामांकन अनुपात (GER) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्राथमिक स्तर पर GER 78.4% (2010-11) से बढ़कर 98.3% (2022-23) हो गई; उच्च प्राथमिक स्तर पर 63.2% से 91.7% तथा माध्यमिक स्तर पर 45.6% से 80.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह सुधार SSA के 'घर के निकट विद्यालय' की नीति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति का संयुक्त परिणाम है (MHRD, 2019; Kumar, 2017) [13]।

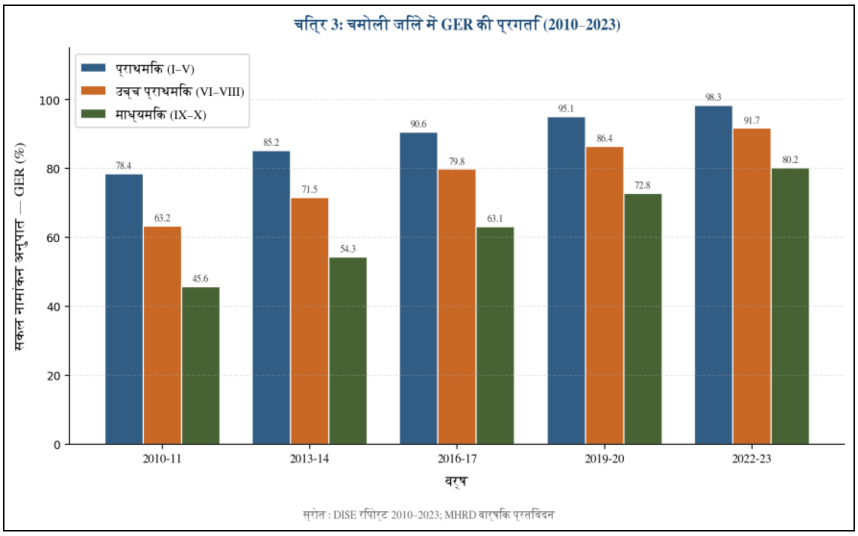

स्रोत: DISE रिपोर्ट 2010-2023

चित्र 2: चमोली जिले में GER की प्रगति (2010-2023) |

7.3 विद्यालय छोड़ने के कारण

ड्रॉप-आउट दर 22.8% (2000-01) से घटकर 5.7% (2022-23) हो गई है। तथापि जो बच्चे अभी भी विद्यालय छोड़ रहे हैं, उनके कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े निम्न पाई-चार्ट (चित्र 3) में दर्शाये गये हैं:

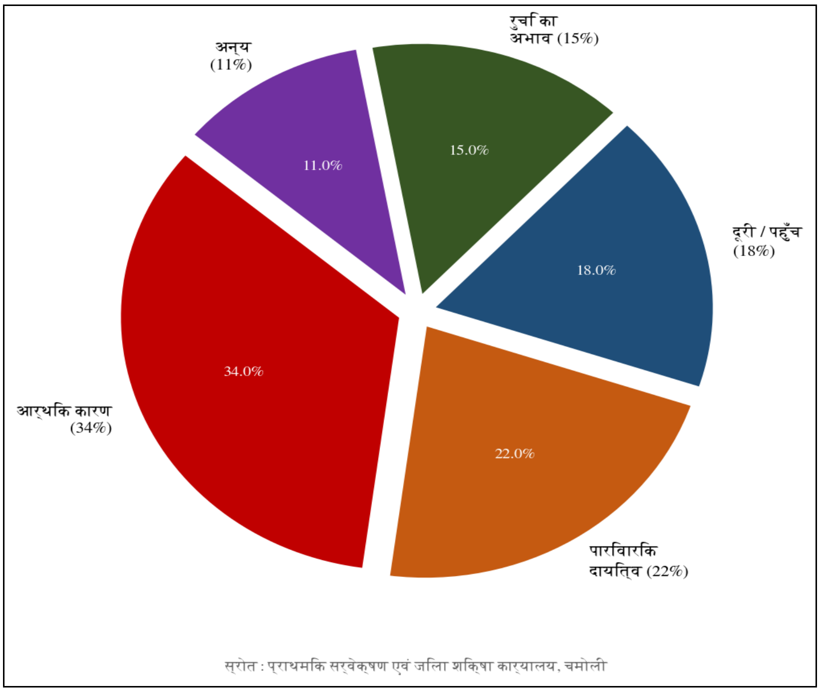

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

चित्र 3: विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण – चमोली (2022-23) |

आर्थिक कारण (34%) एवं पारिवारिक दायित्व (22%) मिलकर 56% ड्रॉप-आउट के लिए उत्तरदायी हैं। दूरी एवं पहुँच (18%) पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्या है जहाँ अनेक बच्चों को 5-7 किमी. पैदल चलकर विद्यालय जाना पड़ता है (Rawat & Negi, 2015; UNICEF, 2019) [26, 30]।

7.4 विद्यालयी अवसंरचना

SSA के अन्तर्गत चमोली जिले में विद्यालयी अवसंरचना में आमूलचूल सुधार हुआ है। निम्न चित्र 4 में 2014-15 एवं 2022-23 की तुलना प्रस्तुत है। पेयजल (88%), शौचालय (82-85%) एवं विद्युत (76%) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु विज्ञान-प्रयोगशाला (38%) एवं ICT सुविधाएँ (34%) अभी भी अपेक्षित स्तर से कम हैं (Jha & Jhingran, 2005; Planning Commission, 2007) [11, 24]।

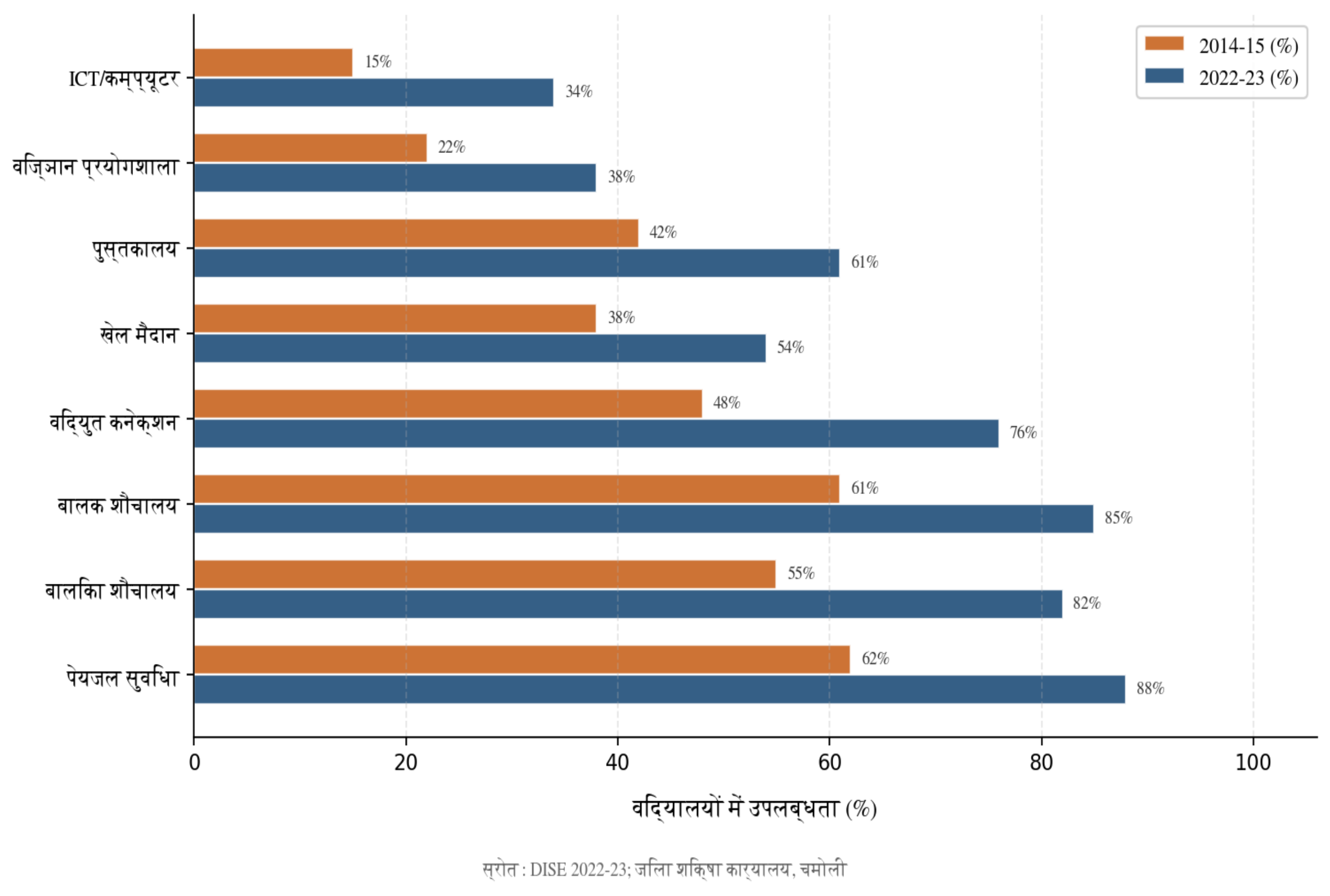

स्रोत: DISE 2022-23

चित्र 4: SSA के अन्तर्गत विद्यालयी अवसंरचना (2014-15 बनाम 2022-23) |

7.5 शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति

SSA के अन्तर्गत 'शिक्षक प्रशिक्षण' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चित्र 5 दर्शाता है कि वर्ष 2010 में मात्र 61% शिक्षक प्रशिक्षित थे जो 2022 तक 89% हो गये। यह सुधार मुख्यतः दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (DLP), सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं DIET (जनपद शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान) की सक्रिय भूमिका के कारण सम्भव हुआ (SCERT Uttarakhand, 2022; NCTE, 2018) [27]।

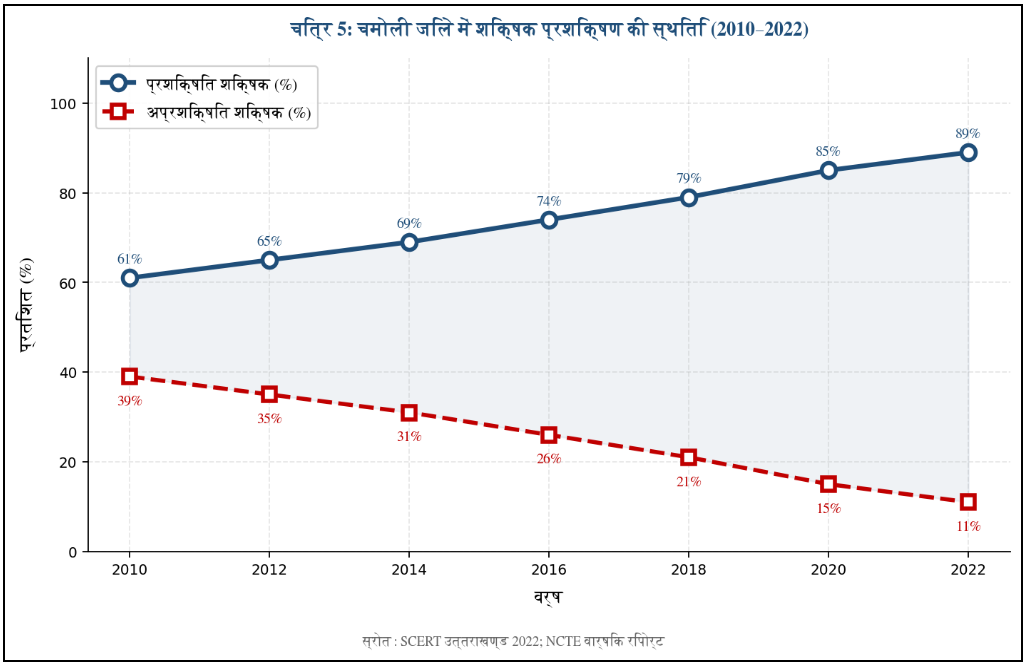

स्रोत: SCERT उत्तराखण्ड

चित्र 5: चमोली जिले में शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति (2010-2022) |

7.6 सामाजिक वर्गानुसार नामांकन

SSA के समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) घटक ने चमोली जिले के SC/ST एवं वंचित वर्गों के नामांकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्र 6 में 2022-23 के नामांकन का सामाजिक वर्गीकरण प्रस्तुत है:

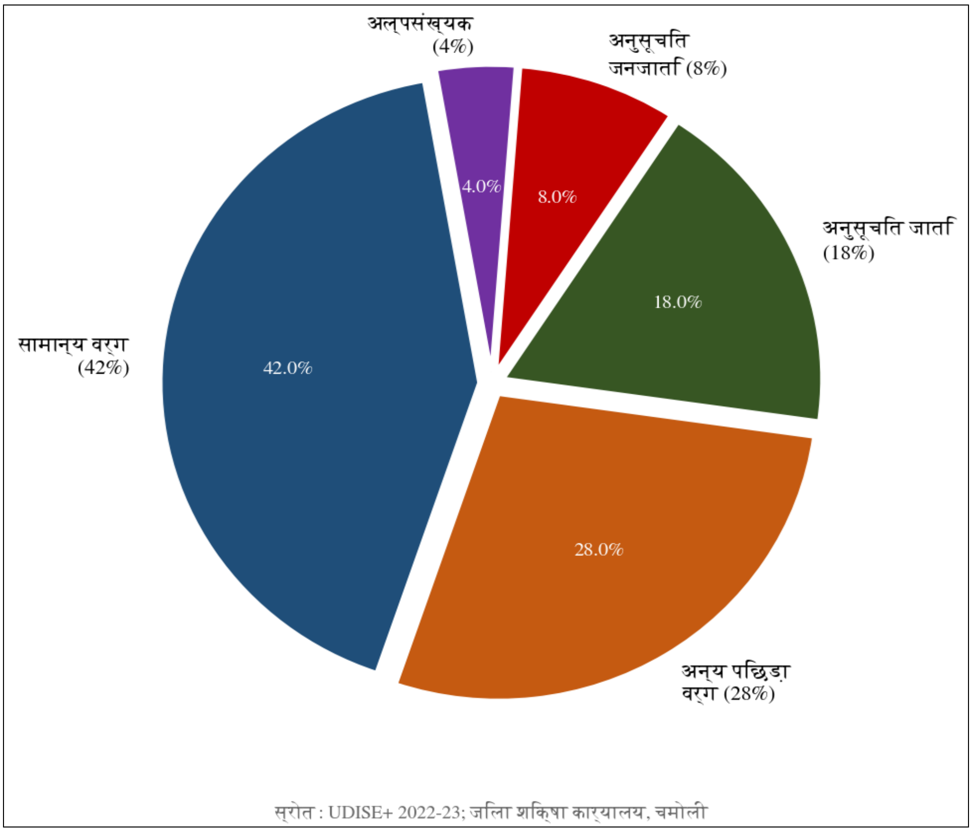

स्रोत: UDISE+ 2022-23

चित्र 6: सामाजिक वर्गानुसार नामांकन वितरण – चमोली (2022-23) |

SC/ST एवं OBC मिलकर 54% नामांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो SSA की समावेशी नीति की सफलता को दर्शाता है। अनुसूचित जाति की बालिका नामांकन दर 2001 के 58.3% से बढ़कर 2022-23 में 87.6% हो गई (Ministry of Education, 2022) [15]।

8. SSA का सामाजिक प्रभाव

8.1 बालिका शिक्षा

SSA के अन्तर्गत 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV)' योजना ने चमोली जिले में बालिका शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया है। बालिका नामांकन अनुपात (GPI) 2001 के 0.84 से बढ़कर 2022-23 में 0.98 हो गया है। शौचालय-निर्माण एवं 'छात्रावास' सुविधाओं ने बालिका नामांकन में निर्णायक योगदान दिया (UNESCO, 2014; MHRD, 2022) [32]।

8.2 SC/ST एवं वंचित वर्ग

चमोली में अनुसूचित जाति की बालिका नामांकन दर 87.6% (2022-23) तक पहुँच गई है। विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (STC) के माध्यम से ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया जो कभी विद्यालय नहीं गये थे (Ministry of Education, 2022; Govinda, 2011) [15, 10]।

8.3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN)

SSA के 'समावेशी शिक्षा' घटक के अन्तर्गत 2022-23 में 94% CWSN बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरण एवं रैम्प-निर्माण ने यह सम्भव किया (DEO Chamoli, 2023)।

8.4 मध्याह्न भोजन एवं उपस्थिति

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) ने उपस्थिति दर एवं नामांकन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाला है। सर्वेक्षण में 78% अभिभावकों ने इसे बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का प्रमुख कारण बताया (Drèze & Goyal, 2003; MHRD, 2019) [6]।

9. चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

उपलब्धियों के बावजूद चमोली जिले में SSA के क्रियान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं:

तालिका 3: SSA क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ – चमोली जिला

क्र.	चुनौती	विवरण एवं प्रभाव
1	भौगोलिक दुर्गमता	दूरदराज गाँवों तक शिक्षकों-संसाधनों की पहुँच कठिन; मौसमी विद्यालय-बंदी
2	शिक्षकों की कमी	पर्वतीय क्षेत्र में पोस्टिंग की अनिच्छा – बड़ी संख्या में पद रिक्त
3	मौसमी प्रवास	परिवारों के पलायन से बच्चों की पढ़ाई में अनियमितता
4	गुणवत्ता बनाम नामांकन	नामांकन बढ़ा किन्तु अधिगम-स्तर अपेक्षित नहीं (ASER, 2022)
5	बहु-श्रेणी शिक्षण	एकल शिक्षक को एकसाथ कई कक्षाएँ पढ़ानी पड़ती हैं
6	डिजिटल विभाजन	इन्टरनेट व ICT सुविधाओं का अभाव; स्मार्ट क्लास की कमी
7	वित्तीय अनियमितता	धनराशि के समयबद्ध एवं पारदर्शी उपयोग में कठिनाइयाँ
8	ड्रॉप-आउट (माध्यमिक)	कक्षा 6-8 के बाद ड्रॉप-आउट दर अभी भी चिन्ताजनक

10. सुझाव एवं सिफारिशें

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत हैं:

1. पर्वतीय जिलों के लिए SSA/समग्र शिक्षा में विशेष 'हिमालयी शिक्षा घटक' जोड़ा जाये जो स्थानीय भूगोल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हो।
2. दुर्गम क्षेत्रों में 'आवासीय विद्यालयों' एवं 'छात्रावासों' की संख्या बढ़ाई जाये तथा मौसम के अनुसार विद्यालय-कैलेण्डर में लचीलापन लाया जाये।
3. प्रशिक्षित शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए विशेष प्रोत्साहन-भत्ता, अतिरिक्त वेतन-वृद्धि एवं कैरियर-लाभ दिये जायें।
4. ग्राम शिक्षा समितियों (VEC) को अधिक वित्तीय स्वायत्तता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाये; सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत रूप दिया जाये।
5. डिजिटल शिक्षा के लिए 'ई-विद्यालय', सैटेलाइट शिक्षण एवं 'ऑफलाइन-फर्स्ट' ICT मॉडल का विस्तार किया जाये।

6. प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए 'मोबाइल स्कूल' अथवा 'सीजनल आवासीय केन्द्र' की स्थापना की जाये।
7. ASER जैसे मूल्यांकन उपकरणों का नियमित उपयोग करते हुए 'उपचारात्मक शिक्षण' (Remedial Teaching) को अनिवार्य बनाया जाये।
8. शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 'लर्निंग आउटकम' मिशन को जनपद स्तर पर लागू किया जाये।

11. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान ने चमोली जिले के ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्रसार में एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। नामांकन दर में ऐतिहासिक वृद्धि, ड्रॉप-आउट दर में उल्लेखनीय कमी, विद्यालयी अवसंरचना का व्यापक विकास, बालिका शिक्षा में सुधार, SC/ST वर्गों की समावेशिता एवं शिक्षक-प्रशिक्षण में प्रगति – ये सभी SSA के सुस्पष्ट एवं मापनीय सकारात्मक प्रभाव हैं। किन्तु भौगोलिक दुर्गमता, शिक्षकों की कमी, प्रवासन की समस्या, डिजिटल विभाजन एवं शिक्षा की निम्न गुणवत्ता अभी भी गम्भीर चुनौती बनी हुई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नीति-निर्माता एवं प्रशासन इन चुनौतियों को केन्द्र में रखकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सक्रिय एवं नवोन्मेषी रणनीतियाँ अपनायें। तभी 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' का संवैधानिक स्वप्न साकार हो सकेगा।

12. सन्दर्भ

1. Annual Status of Education Report (ASER). Annual Status of Education Report (Rural) 2018. New Delhi: Pratham Education Foundation; c2018.
2. Annual Status of Education Report (ASER). Annual Status of Education Report (Rural) 2022. New Delhi: Pratham Education Foundation; c2022.
3. Census of India. Primary Census Abstract: Chamoli District, Uttarakhand. New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner of India; c2011.
4. District Education Office Chamoli. Annual Education Report 2022-23: Chamoli. Chamoli (Uttarakhand): District Education Office; c2023.
5. District Information System for Education (DISE). District Report Cards: Chamoli District, 2022-23. New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration; c2023.
6. Drèze J, Goyal A. The future of mid-day meals. Economic and Political Weekly. 2003;38(44):4673-4683.
7. Drèze J, Sen A. India: Development and Participation. New Delhi: Oxford University Press; c2002.
8. Government of India. The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002. New Delhi: Ministry of Law and Justice; c2002.
9. Government of India. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. New Delhi: Ministry of Law and Justice; c2009.
10. Govinda R, editor. Who Goes to School? Exploring Exclusion in Indian Education. New Delhi: Oxford University Press; c2011.
11. Jha J, Jhingran D. Elementary Education for the Poorest and Other Deprived Groups: The Real Challenge of Universalisation. New Delhi: Centre for Policy Research; c2005.
12. Kumar K, Priyam M, Saxena S. Looking beyond the smokescreen: DPEP and primary education in India. Economic and Political Weekly. 2001;36(7):560-568.
13. Kumar R. Universalisation of elementary education in India: Progress and challenges under SSA. Journal of Education and Practice. 2017;8(14):112-120.
14. Mehta AC. Elementary Education in India: Analytical Report 2013-14. New Delhi: National University of Educational Planning and Administration; c2014.
15. Ministry of Education, Government of India. UDISE+ 2021-22: Flash Statistics. New Delhi: Ministry of Education; c2022.
16. Ministry of Education, Government of India.

Annual Report 2022-23. New Delhi: Department of School Education and Literacy; c2023.
17. Ministry of Human Resource Development. Sarva Shiksha Abhiyan: A Programme for Universal Elementary Education. New Delhi: Ministry of Human Resource Development; c2001.
18. Ministry of Human Resource Development. Sarva Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation. New Delhi: Ministry of Human Resource Development; c2007.
19. Ministry of Human Resource Development. Samagra Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation. New Delhi: Ministry of Human Resource Development; c2018.
20. Ministry of Human Resource Development. Annual Report 2018-19. New Delhi: Ministry of Human Resource Development; c2019.
21. Ministry of Education. National Achievement Survey (NAS) 2021: District-wise Report. New Delhi: Ministry of Education; c2022.
22. National Council of Educational Research and Training. National Curriculum Framework for School Education: Consultative Document. New Delhi: NCERT; c2020.
23. National Council for Teacher Education. Annual Report 2017-18. New Delhi: National Council for Teacher Education; c2018.
24. Planning Commission of India. Report of the Working Group on Elementary Education and Literacy for the XI Five Year Plan. New Delhi: Government of India; c2007.
25. Ramachandran V. Gender and Social Equity in Primary Education: Hierarchies of Access. New Delhi: Sage Publications; c2004.
26. Rawat PS, Negi MS. Educational development in the hill districts of Uttarakhand: Issues and challenges. Himalayan Journal of Sociology and Anthropology. 2015;7:1-18.
27. State Council of Educational Research and Training Uttarakhand. State Report on Teacher Training 2021-22. Dehradun: SCERT Uttarakhand; c2022.
28. Singh AK. Sarva Shiksha Abhiyan in hill regions of Uttarakhand: An assessment. Indian Journal of Educational Research. 2011;2(1):45-60.
29. Tilak JBG. Absence of policy or policy of absence: Primary education in India. India International Centre Quarterly. 2004;30(3-4):171-183.
30. UNICEF. Children in India 2019: A Statistical Appraisal. New Delhi: UNICEF India; c2019.
31. UNICEF India. Out-of-School Children in India: A Study on Trends and Determinants. New Delhi: UNICEF Country Office; c2020.
32. UNESCO. Education for All: Teaching and Learning - Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report. Paris: UNESCO; c2014.
33. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education. Paris: UNESCO; c2020.
34. Yadav RK, Srivastava DK. Status of elementary education in Uttarakhand: A district level analysis. Educational Confab. 2016;5(2):1-12.
35. World Bank. Project Appraisal Document: Sarva Shiksha Abhiyan II (SSA II). Report No. 44054-IN. Washington (DC): World Bank; c2008.
36. Zymelman M, DeStefano J. Primary School Teachers' Salaries in Sub-Saharan Africa. World Bank Discussion Paper No. 45. Washington (DC): World Bank; c1993.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.